***Date*:** 24-09-20
***Publication*:** Business Standard
***Edition*:** Kolkata

Coal India finalises ₹5,900-crore heavy machinery contracts to boost production

Coal India, the world's largest miner, has finalised contracts for heavy earth moving equipment worth over ₹5,900 crore to ramp up production, its Chairman Pramod Agrawal said on Wednesday. The miner is also planning a capex of ₹10,000 crore during the current fiscal year.

Early this year, the company had said it was looking at spending around ₹7,000 crore on heavy equipment to bolster production.

"Heavy earth moving machinery worth over ₹5,900 crore has been finalised for augmentation of coal production and improving age profile of equipment," Agrawal told shareholders at the annual general meeting.

To make a quantum jump in output, Mine Development and Operator documents for open cast and underground mines have also been finalised with valuable input from all stakeholders approved by the CIL board, he said. Four tenders have already been floated, of which three are for Central Coalfields and one for Mahanadi Coalfields with 20-25 years of contract period.

Tenders for 10 more mines would be floated shortly, and the documents for abandoned mines are under review to make use of advanced technology to augment production further, he said in his address. PTI

***Date*:** 25-09-20
***Publication*:** The Times of India
***Edition*:** Kolkata

CIL forms SPVs to set up rail infra

Kolkata: Coal India (CIL), in a bid to evacuate increased quantity of coal through rail route from potentially high-yielding opencast mines of its Chhattisgarh-based subsidiary South Eastern Coalfields (SECL), has formed two special purpose vehicles (SPV) for construction of rail lines. Chhattisgarh East West Railway (CEWRL) to construct a 135 km east-west rail corridor at an estimated cost of Rs 4,970 crore and the other a Rs 3,055 crore SPV called Chhattisgarh East Rail (CERL) to develop 136 km east rail corridor. CERL is already partly operational.

An official pointed out that two large value tenders for the construction of 135-km line from Gevra Road to Pendra Road, to be developed by CEWRL have been floated recently. The JV partners in CEWRL include SECL representing CIL and ministry of coal with 64% stake and IRCON representing Indian Railways with 26%. Chhattisgarh State Industrial Development Corporation is the third partner chipping in with the rest 10%. TNN

***Date*:** 25-09-20
***Publication*:** Sanmarg
***Edition*:** Asansol

कोल इंडिया की 11 माइंस से पावर प्लांट के लिए सीबीएम का प्रोडक्शन होगा : आरएन सोम

सन्मार्ग संवाददाता

सांकतोड़िया : कोल इंडिया की 11 माइंस को सीबीएम के उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया है। सीबीएम (कोल बोर्ड मिथेन) व ओएनजीसी दोनों ही कंपनियां ज्वाइंट रूप से कोयले के भंडार में मौजूद जहरीली गैस का दोहन कोल उत्पादन करने के पहले किया जायेगा। इसके बाद ही कोल प्रोडक्शन किया जायेगा। इससे माइंस एक्सीडेंट की आशंका काफी कम हो जायेगी। पहले ओएनजीसी गैस का उपयोग करेगा, फिर कोल इंडिया उनसे कोयला निकालेगा। महाप्रबंधक प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग आरएन सोम ने बताया कि ईसीएल की तीन एरिया सतग्राम, कनुस्तोरिया एवं श्रीपुर एरिया क्षेत्र की माइंस इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि तीनों एरिया में 2.5 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है। मिथेन (सीएमएम) प्रोजेक्ट के लिए जारी टेंडर में किसी भी एजेंसी ने हिस्सा नहीं लिया, इसलिए ईसीएल प्रबंधन ने दोबारा टेंडर निकाला है। मालूम हो कि कोल इंडिया के अलावा ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पर्वतपुर कोयला ब्लॉक विकसित किया जायेगा। झारखंड के झरिया, बोकारो के पर्वतपुर, नार्थ कर्णपुरा में इसका बड़ा भंडार है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में भी गैस का भंडार है। इससे पावर प्लांटों में बिजली उत्पादित की जायेगी। कई और प्रोजेक्ट लगाने पर विचार किया जा रहा है। मुनीडीह में कोल बेड मिथेन, कोल माइंस मिथेन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। मुनीडीह क्षेत्र में मौजूद मिथेन गैस के भंडार के दोहन के साथ-साथ खदान हादसों में कमी आयेगी। लगभग 60 करोड़ की लागत से दो मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए प्लांट लगाने की योजना है। सीबीएम का भंडार रानीगंज में 2.5 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस, झरिया में 23 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस, नार्थ कर्णपुरा में 28 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस, बोकारो में 23 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है। सीबीएम (कोल बेड मिथेन) ब्लॉक के लिए आयोजित ग्लोबल प्री एनआईटी मीट में देश के साथ-साथ विदेशी कंपनियों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। आस्ट्रेलिया एवं पोलैंड की सीबीएम दोहन करने वाली कुछ कंपनियां के साथ-साथ भारत की अडाणी, एस्सार ऑयल, जेएस माइनिंग सहित कुल 12 कंपनियां ने भाग लिया है। सीएमपीडीआईएल की ओर से ऑनलाइन प्रीएनआईटी मीट का आयोजन 21 सितंबर को किया गया था। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के साथ-साथ झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए भी प्रीएनआईटी मीटिंग हुई। सीएमपीडीआईएल के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मीटिंग उत्साहजनक रही। कंपनियों ने कुछ शर्तों में रियायत की मांग करते हुए कई सुझाव दिए हैं। प्री एनआईटी मीटिंग के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि रानीगंज में सीबीएम का कोल सीम में बड़ा भंडार है। दोहन होने से रानीगंज कोयला क्षेत्र कोयले के साथ-साथ गैसीय ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। सीबीएम दोहन को लेकर कोयला मंत्रालय गंभीर है। सीबीएम का कई उपयोग है। सीएनजी, एलपीजी के साथ-साथ मिथेन का औद्योगिक उपयोग भी है। इससे उद्योग तक चलाए जा सकते हैं। अब सीएमपीडीआईएल को क्रियान्वयन एजेंसी बना मिथेन दोहन के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है।

***Date*:** 27-09-20
***Publication*:** Sanmarg
***Edition*:** Asansol

मांग व पूर्ति में 2.5 मिलियन टन कोयला की कमी को दूर करने की बड़ी तैयारी

सांकतोड़िया : हर साल 1.5 लाख करोड़ टन कोयला का आयात कम कर देश आत्मनिर्भर बन सके तथा देश में कोयला उत्पादन बढ़ाकर आयात में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्पादन पर खर्च के बजट को सरकार ने दोगुना करते हुए एक लाख करोड़ रुपये कर दिया है। पहले यह राशि 50 हजार करोड़ थी। कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसके संकेत भी दिए थे। सरकार की मंशा साफ है कि करीब 1.5 लाख करोड़ का जो कोयला आयात किया जा रहा है, उसमें हर हाल में कमी लाई जाए। इसलिए जो भी संसाधन कोयला उत्पादन के लिए जरूरी है, उस पर काम किया जाए। कोल इंडिया को भी मजबूत करने की दिशा में कोयला ब्लॉक का आवंटन किए जा रहा है। उन कोयला ब्लॉक पर जल्द से जल्द खनन करने का निर्देश दिया जा रहा है। देश में कोयला की मांग और पूर्ति में करीब 2.5 मिलियन टन का अंतर है। इस खाई को पाटना केंद्र सरकार का मकसद है ताकि कोयला क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए 60 कोयला ब्लॉक पर काम किया जा रहा है। सरकार ने अगले चार साल में 405 मिलियन टन कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी करने के करीब 200 प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही पांच दर्जन नए प्रोजेक्ट खोलने की भी योजना है।

कोल डिस्पैच बढ़ाने के लिए 18000 करोड़ खर्च करेगी कोल इंड़िया

कोल इंडिया में कोयला डिस्पैच बढ़ाने को लेकर कोयला मंत्रालय 18 हजार करोड़ रुपये कोयला डिस्पैच को गति देने के लिए आधारभूत संरचना विकास के मद में खर्च करेगी। इसमें साइलो, रेल साइडिंग, रेल लाइन बिछाने आदि शामिल है। कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी गंभीरता दिखाई है। कोयला कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करें।

***Date*:** 27-09-20
***Publication*:** Hari Bhoomi
***Edition*:** Korba

कोल इंडिया ने 59 सौ करोड़ की मशीनरी को दिया अंतिम रुप

हरिभूमि न्यूज ⏭ कोरबा

कोल इंडिया के चेयरमेन प्रमोद अग्रवाल ने बुधवार को कहा है कि कंपनी ने उत्पादन बढ़ाने को लेकर चट्टानों, मिट्टी और भारी सामानों को हटाने वाले क्रेन समेत अन्य भारी उपकरणों के लिए 59 सौ करोड़ रुपए मूल्य के अनुबंध को अंतिम रुप दे दिया है। जिसके बाद जिले में एसईसीएल के गेवरा खदान में भी 33 भारी मशीनरी भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी कोल इंडिया चालू वित्तीय वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपए पूंजी व्यय की योजना बना रहा है। इससे पहले कंपनी ने कहा था कि वह उत्पादन बढ़ाने को लेकर करीब 7 हजार करोड़ रुपए भारी उपकरणों पर खर्च करने पर विचार कर रही है। कोल इंडिया के चेयरमेन प्रमोद अग्रवाल ने शेयरधारकों की सालाना बैठक में कहा है कि कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए 59 सौ करोड़ रुपए मूल्य की भारी मशीनों के आर्डर को अंतिम रुप दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए खुले खान और भूमिगत खदानों के लिए खान विकास और परिचालक (एमडीओ) दस्तावेज को भी शेयरधारकों से राय लेकर अंतिम रुप दिया गया है। इस बारे में निदेशक मंडल की मंजूरी मिल गई है। 20 से 25 साल की अनुबंध अवधि के साथ 4 निविदाएं जारी की गई हैं इनमें से 3 सेंट्रल कोलफील्ड्स के लिए एक महानदी कोलफील्ड के लिए है। श्री अग्रवाल ने कहा है कि जल्दी ही 10 और खदानों के लिए निविदा जारी की जाएगी। इसके अलावा छोड़े गए खदानों से उत्पादन बढ़ाने को लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है।

खास बातें

- 10 हजार करोड़ रुपए पूंजी व्यय की योजना
- जल्द ही 10 और खदानों के लिए जारी की जाएगी निविदा

गेवरा खदान को मिलेंगे 7 डम्पर, बढ़ेगा उत्पादन

जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी खुली कोयला खदान गेवरा के लिए 150 टन क्षमता वाले सात डम्पर की खरीदी की जाएगी। इन डम्परों की कीमत 150 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) से करार किया है। खरीदी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी डम्पर गेवरा खदान को दिए जाएंगे। जो कोयला खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गेवरा ओपनकास्ट परियोजना में डम्पर को ट्रायल के तौर पर उतारा जाएगा। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी एसईसीएल की चार परियोजनाएं जिले में स्थित है। जिसमें से गेवरा परियोजना सबसे अधिक उत्पादन करने वाली परियोजना है। बीते वित्तीय वर्ष में एसईसीएल गेवरा ने 45 मिलियन टन के सौ फीसदी उत्पादन लक्ष्य को हासिल किया था। इस वित्तीय वर्ष गेवरा को 49 मिलियन टन का टारगेट मिला है। साल दर साल गेवरा परियोजना के उत्पादन लक्ष्य में बढ़ोतरी हो रही है। इस लिहाज से गेवरा को संसाधन उपलब्ध कराए जाने की कवायद भी कंपनी कर रही है। इसी कड़ी में गेवरा के लिए 7 नए डम्पर की खरीदी की जा रही है। इन डम्परों से 150 टन क्षमता अनुरूप खनन का काम हो सकेगा। जिससे शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाली परियोजना के उत्पादन में और भी बढ़ोतरी होगी।